[2014] 13 एस. सी. आर. 642

उत्तर प्रदेश और ओ. आर. एस. का राज्य।

वी.

पवन कुमार द्विवेदी और ओआरएस,

(2006 की सिविल अपील सं. 3989)

2 सितंबर, 2014

[आर. एम. लोधा, सीजेआई, जगदीश सिंह खेहर,

जे. चेलामेश्वर, ए. के. सिकरी और

रोहिंटन फाली नरीमन, जे. जे.]

सेवा कानून-वेतन-उत्तर प्रदेश जूनियर हाई

कर्मचारी) अधिनियम, 1978। 2 (जे) और 10-उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972-मान्यता प्राप्त कनिष्ठ की तीन श्रेणियाँ

उच्च विद्यालय; (एक) कक्षा I से VIII तक, अर्थात कक्षा I

पांचवीं (जूनियर बेसिक स्कूल) और इसी तरह छठी से आठवीं कक्षा तक

(सीनियर बेसिक स्कूल), (दो) ऊपर के रूप में एक स्कूल और उन्नत

उच्च विद्यालय या मध्यवर्ती मानक और (तीन) कक्षाओं के लिए

VI से VIII (सीनियर बेसिक स्कूल) शुरू में बिना जूनियर बेसिक के

स्कूल (कक्षा I से V) का उक्त स्कूल का हिस्सा होना-विवाद

उन विद्यालयों की तीसरी श्रेणी के संबंध में जहाँ कक्षा I से लेकर

वीं को स्कूलों को मान्यता प्राप्त करने के बाद जोड़ा जाता है जो कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त हैं

VI से VIII-प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों की पात्रता

एस के लाभ के लिए ऐसे स्कूलों में I से V तक। 10 1978 के अधिनियम -

क्या निजी रूप से प्रबंधित प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और

निजी रूप से प्रबंधित उच्च विद्यालयों के प्राथमिक वर्ग हैं -

राज्य सरकार से अपना वेतन प्राप्त करने के लिए पात्र

आयोजित किया गया: यदि एक जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा I से V) जोड़ा जाता है

किसी मान्यता प्राप्त व्यक्ति को आवश्यक मान्यता प्राप्त करने के बाद और

सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा VI से VIII), तो निश्चित रूप से

ऐसा जूनियर बेसिक स्कूल एक का अभिन्न अंग बन जाता है। प्राथमिक विद्यालय जिसमें पहली से आठवीं तक की कक्षाएँ हैं-अभिव्यक्ति

" 1978 के अधिनियम में 'जूनियर हाई स्कूल' का उल्लेख करने का इरादा है -

बुनियादी शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल, अर्थात, तक की शिक्षा

बुनियादी विद्यालय और वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय भी अलग-अलग या एक साथ एक ही बोर्ड के अधीन हैं, अर्थात

बुनियादी शिक्षा बोर्ड, 1972 के अधिनियम के अनुसार-जूनियर हाई

स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षा I से V तक शामिल हैं जब वे हैं इसके बाद एक वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय (छठी से आठवीं कक्षा) में खोला गया

अलग मान्यता प्राप्त करना और जिसके लिए नहीं हो सकता है

सरकार द्वारा सहायता अनुदान का एक अलग आदेश होना चाहिए।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1 . मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हो सकते हैं

तीन प्रकार केः (एक) कक्षा I से VIII तक, अर्थात, कक्षाएँ

I से V (जूनियर बेसिक स्कूल) और इसी तरह कक्षा VI से लेकर VIII (सीनियर बेसिक स्कूल), (दो) ऊपर के रूप में एक स्कूल और

उच्च विद्यालय या मध्यवर्ती मानक में उन्नयन और (तीन) कक्षा छठी से आठवीं (वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय) शुरू में

कोई जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा I से V) हिस्सा नहीं है

उक्त विद्यालय से। [पैरा 43] [672-डी]

2. यदि एक जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा I से V) जोड़ा जाता है

मान्यता प्राप्त व्यक्ति को आवश्यक मान्यता प्राप्त करने के बाद और सहायता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा VI से VIII), तब

निश्चित रूप से ऐसा जूनियर बेसिक स्कूल अभिन्न अंग बन जाता है। एक विद्यालय, अर्थात प्रथम से आठवीं कक्षा वाले बुनियादी विद्यालय।

इसका संकीर्ण अर्थ देना उचित नहीं है।

अभिव्यक्ति "जूनियर हाई स्कूल"। उस विधानमंडल ने उपयोग किया

अभिव्यक्ति जूनियर हाई स्कूल और बुनियादी नहीं

उत्तर प्रदेश बेसिक में उपयोग और परिभाषित स्कूल

शिक्षा अधिनियम, 1972 महत्वहीन है। यह दृश्य मजबूत है।

इस तथ्य से कि उत्तर प्रदेश जूनियर की धारा 2 (जे) में उच्च विद्यालय (शिक्षकों के वेतन का भुगतान और

अन्य कर्मचारी) अधिनियम, 1978, में परिभाषित अभिव्यक्तियाँ

1972 का अधिनियम शामिल किया गया है। [पैरा 44] [672-एच; 673-ए-डी]

3. इस तर्क में योग्यता है कि स्कूल

जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट होना

[2014]

13 एस सी आर।

स्कूल या तो अलग से या एक साथ एक ही के अंतर्गत आते हैं।

बोर्ड, अर्थात बुनियादी शिक्षा बोर्ड, 1972 के अनुसार

एक्ट करें। यह आयोजित किया जाता है, जैसा कि यह होना चाहिए, कि जूनियर हाई स्कूल

अनिवार्य रूप से कक्षा I से V तक शामिल हैं जब वे खोले जाते हैं

एक वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय (कक्षा VI से VIII) में

अलग मान्यता प्राप्त करना और जिसके लिए हो सकता है

द्वारा अनुदान-सहायता का एक अलग आदेश नहीं होना

सरकार। [पैरा 46] [674-सी-ई]

विनोद शर्मा और अन्य बनाम। शिक्षा निदेशक

(बेसिक) यू. पी. और अन्य (1998) 3 एस. सी. सी. 404: 1998 (2) एससीआर 382-पुष्टि की गई।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य

जे. पी. उन्नीकृष्णन बनाम एपी राज्य (1993) I एससीसी 645 : 1993 (1) एस. सी. आर. 594; एच. पी. राज्य बनाम। एचपी राज्य

मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय प्रबंधन समिति

(1995) 4 एस. सी. सी. 507; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू राम

नगर महापलिका, कानपुर बनाम। विभा शुक्ला (श्रीमती) और अन्य (2007) 15 एससीसी 161: 2007 (7)

एस. सी. आर. 488; बारास बनाम। एबरडीन स्टीम ट्रैलिंग

और मछली पकड़ने वाली कंपनी 1933 ऑल ई. आर. 52; गलाघेर

वी. चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर-डे सेंट्स

(2008) 4 सभी ई. आर. 640; डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड v.

उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 652: 1961

एस. सी. आर. 242; सिरसिल्क बनाम। वस्त्र समिति और

अन्य 1989 पूरक 1 एस. सी. सी. 168: 1988 (2) पूरक।

एस. सी. आर. 880; अध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण

वी. प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड और

अन्य (2007) 8 एस. सी. सी. 705: 2007 (6) एससीआर 799;

यू. पी. राज्य बनाम प्रबंधन समिति, माता तपेश्वरी (2010) 1 एस. सी. सी. 239 2009 (15)

एस. सी. आर. 1276-संदर्भित।

यू. पी. राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी

मैक्सवेल 'क़ानूनों की व्याख्या पर', 10 वीं संस्करण।

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ:

1998 (2) एससीआर 382

पुष्टि पैरा 2

2002 (3) पूरक। एससीआर 587

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 10

1993 (1) एससीआर 594

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 10

(1995) 4 एससीसी 507

पैर

ा 10

संदर्भित किया गया है

1961 एससीआर 679

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 11

2007 (7) एससीआर 488

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 11

1933 सभी ईआर 52

पैर

ा 12

संदर्भित किया गया है

(2008) 4 सभी ईआर 640

पैर

ा 12

संदर्भित किया गया है

1961 एससीआर 242

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 12

1988 (2) पूरक। एससीआर 880

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 12

2007 (6) एससीआर 799

संदर्भित किया गया है

पैर

ा 12

2009 (15) एससीआर 1276

पैर

ा 17

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

3989 2006 से।

19.07.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से पारित

इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष

2000 की अपील सं. 30।

के साथ

सिविल अपील सं। 3990 , 3991 , 3992 , 3993 , 3994 2006 का

& 6111 2008 से।

पी. पी. राव, सुनील गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. आर. शमशाद,

शशांक सिंह, यू. उमर, विक्रांत यादव, रोहित, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2014]

13 एस सी आर।

M.P.Raju, पी. जॉर्ज गिरी, जेम्स पी. थॉमस, के. के. मिश्रा,

राघवेंद्र शुक्ला, गौरव जैन, आभा जैन, एन. के. जैन, विवेक

विश्नोई, मुकेश वर्मा, पवन कुमार शुक्ला, यश पाल ढींगरा, ई. सी. विद्या सागर, शंकर दिवाते, आर. डी. उपाध्याय,

पूर्णिमा भट, प्रिया पुरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एम. लोधा, सीजेआई। 1. आम सवाल

सात अपीलों के इस समूह में विचार यह है कि क्या

निजी रूप से प्रबंधित प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक निजी रूप से प्रबंधित उच्च विद्यालयों के वर्ग पात्र हैं

राज्य सरकार से उनका वेतन प्राप्त करते हैं?

2. इन अपीलों को पहले दोनों के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था-न्यायाधीश

बेंच। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रावधानों पर ध्यान देते हुए स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज (वेतन का भुगतान)

शिक्षक और अन्य कर्मचारी) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 1971) अधिनियम '), उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम, 1972 (संक्षेप में'

1972 अधिनियम '), उत्तर प्रदेश ने बुनियादी विद्यालयों को मान्यता दी

(शिक्षकों और अन्य की भर्ती और सेवा की शर्तें

शर्तें) नियम, 1975 (संक्षेप में '1975 नियम'), उत्तर

प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (शिक्षकों के वेतन का भुगतान)

और अन्य कर्मचारी) अधिनियम, 1978 (संक्षेप में 1978 अधिनियम),

उत्तर प्रदेश ने बुनियादी विद्यालयों (जूनियर हाई) को मान्यता दी

विद्यालय) (शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1978 (संक्षेप में '1978 नियम'), दो-न्यायाधीश पीठ

महसूस किया कि विनोद मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

शर्मा 1 को पुनर्विचार की आवश्यकता थी।

3. दिनांकित संदर्भ आदेश का प्रासंगिक भाग

08.09.2006 * इस प्रकार पढ़ता है:

" वर्तमान अपीलों में, प्रस्तुतियाँ जो समान थीं

विनोद शर्मा द्वारा दायर रिट याचिकाओं में उठाए गए लोगों के लिए 1

1 विनोद शर्मा और अन्य बनाम। शिक्षा निदेशक (बुनियादी) उत्तर प्रदेश और अन्य; [(1998) 3 एससीसी 404]

* (2006) 7 एस. सी. सी. 745 यू. पी. राज्य बनाम

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

और उच्च न्यायालय के समक्ष और विशेष अवकाश में अन्य

इस न्यायालय में याचिकाओं को दोहराया और दोहराया गया है।

जिस बात पर प्रकाश डाला गया है वह यह है कि ध्यान रखना विभिन्न सरकारी आदेशों के लिए, यह काफी होगा

यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार का इरादा कभी नहीं था कि विभिन्न जूनियर बेसिक के प्राथमिक अनुभागों को लाएं

स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज

वेतन भुगतान अधिनियम, 1978 के दायरे में और

कि एक जानबूझकर और कर्तव्यनिष्ठ निर्णय था,

इसलिए, "जूनियर बेसिक स्कूलों" के इलाज में बनाया गया

स्कूलों की श्रेणी जिन्हें दायरे में लाया गया था वेतन भुगतान अधिनियम, 1978।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "जूनियर बेसिक स्कूल" और

" जूनियर हाई स्कूलों के साथ अलग व्यवहार किया गया, हाई

ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय और उसके बाद यह न्यायालय

इस तथ्य से प्रभावित कि कुछ स्कूलों ने शिक्षा प्रदान की

कक्षा I से X तक एक एकल इकाई के रूप में, हालांकि, समान

विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया था, जैसे, प्राथमिक

अनुभाग, जूनियर हाई स्कूल अनुभाग, जो थे जूनियर बुनियादी अनुभाग बनाने के लिए एक साथ संयुक्त

कक्षा I से VIII तक, और हाई स्कूल अनुभाग में शामिल हैं

एक मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्थान शामिल है, उक्त संस्थान प्राथमिक दोनों के लिए शिक्षा प्रदान कर रहा है।

अनुभाग, उच्च विद्यालय अनुभाग, मध्यवर्ती अनुभाग

और बीए अनुभाग। महाविद्यालय इस प्रकार प्रदान कर रहा है

प्रथम श्रेणी से स्नातक स्तर तक की शिक्षा

संस्थान की ओर से डॉ. पाडिया ने कहा कि संस्थान एक इकाई है जिसमें विभिन्न अनुभाग हैं और

संस्थान के शिक्षक अलग-अलग नहीं हैं

अनुभाग लेकिन स्वयं संस्थान के और इसके परिणामस्वरूप कोई सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट नहीं

[2014] 13 एस सी
आर।

उनके बीच भेदभाव किया जा सकता है। यह था। विनोद में दिए गए तर्कों में से एक

शर्मा 'जिसे इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।

हालाँकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय और

ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायालय इस तथ्य की दृष्टि खो चुका है कि

प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को अलग कर दिया गया है

जूनियर हाई स्कूल स्तर और अलग से सौंपा गया उत्तर के रूप में जाने जाने वाले बोर्ड के लिए विभिन्न अधिनियम

प्रदेश बुनियादी शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम की धारा 3,

1972 और उसी बोर्ड को सौंपा गया था

"जूनियर बेसिक स्कूलों" पर नियंत्रण रखने का अधिकार

1975 के नियमों में प्रदान करने वाले संस्थानों के रूप में संदर्भित

पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा।

हमारे विचार में, ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका ने एक

"जूनियर बेसिक स्कूलों" के बीच कर्तव्यनिष्ठ अंतर

और "जूनियर हाई स्कूल" और उन्हें दो के रूप में माना

अलग-अलग घटकों में "जूनियर बेसिक" शामिल हैं शिक्षा "उत्तर प्रदेश राज्य में। तदनुसार,

पहले के सरकारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए भुगतान

वेतन अधिनियम, 1978 में प्राथमिक धाराएँ और/शामिल नहीं थीं।

या 1978 के दायरे में अलग प्राथमिक विद्यालय

एक्ट करें।

बेशक, इसे राज्य की ओर से स्वीकार किया गया है

सरकार कि इस संबंध में छूट दी गई थी

393 जिन स्कूलों से काम करना जारी रखा गया था

राज्य सरकार द्वारा लगातार वेतन। मामले में उक्त विद्यालयों में से राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया

शिक्षकों के वेतन का भुगतान जारी रखना

ऐसे विद्यालयों का प्राथमिक अनुभाग।

उपरोक्त के अलावा, यह श्री द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है।

दिनेश द्विवेदी, स्टेट ऑफ यू. पी. बनाम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील।

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

उत्तर प्रदेश राज्य जो वेतन का भुगतान करता है

मान्यता प्राप्त प्राथमिक संस्थानों के शिक्षकों को होना चाहिए

राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुरूप और इस तरह का भुगतान करने की क्षमता।

संबंधित पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, विनोद शर्मा 1 में इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया कि

मान्यता प्राप्त कनिष्ठ बुनियादी विद्यालयों के प्राथमिक अनुभाग,

जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल इसके हकदार थे

वेतन के भुगतान के तहत उनके वेतन का भुगतान

अधिनियम, 1978, पुनर्विचार के योग्य है।

4. 10.10.2007 पर, इन अपीलों को इसके समक्ष सूचीबद्ध किया गया था

ई-न्यायाधीश पीठ। पीठ ने कहा कि विनोद शर्मा 1

तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया गया था और इसलिए,

ई-अपीलों पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

10.10.2007 का क्रम इस प्रकार है:

" ये अपीलें हमारे सामने संदर्भ पर रखी गई हैं।

माननीय दो न्यायाधीशों द्वारा पारित दिनांक 8/9/2006 का आदेश

तीन न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए विनोद शर्मा और ओआरएस में बेंच। बनाम निदेशक

शिक्षा (बुनियादी) यू. पी. और अन्य। (1998) 3 एससीसी 404, द

विद्वान न्यायाधीशों का विचार था कि निर्णय

विनोद शर्मा (ऊपर) की जरूरतों में प्रस्तुत किया गया

एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार और रखने का निर्देश दिया गया

माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामला

उचित आदेश।

हमने माननीय सीजेआई के आदेशों को पारित होते देखा है

ए. आर. के 14/9/2006 दिनांकित नोट का आधार। (सूची)। में

कहा गया नोट यह कहा गया है कि मामलों को पहले रखा गया है

माननीय सीजेआई ने इसे एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए

तीन माननीय न्यायाधीश।

चूंकि विनोद शर्मा मामले (ऊपर) का फैसला किया गया है

तीन न्यायाधीशों की पीठ, इन अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होना आवश्यक है

[2014]
13 एस सी आर।

एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार किया गया। मामले को पहले रखें।

उपयुक्त आदेशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश

इन अपीलों को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने के लिए

संबंधित मुद्दे पर विचार करना "।
5. इस तरह ये अपीलें सामने आई हैं

इस पीठ के समक्ष विचार।

6. विनोद शर्मा में अपील इस अदालत में पहुंची

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश जिसके द्वारा

उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किया

(बेसिक) यू. पी. और राज्य के अन्य पदाधिकारी वेतन का भुगतान करेंगे

1978 के अधिनियम के तहत अपीलार्थियों को। में आवश्यक तथ्य

विनोद शर्मा 1 मामला जैसा कि इस अदालत ने फैसले में उल्लेख किया है

ये हैं: 58 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, जूनियर हाई स्कूल, देहरादून कैन्ट। वर्ष 1952 में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था

पूर्व सैनिकों, सेवारत सैन्य कर्मियों के बच्चों के लिए और

अधिकारी और नागरिक भी। संस्थान को मिली मान्यता

09.04.1959 से प्रभावी यू. पी. सरकार। द.

अपीलार्थी, विनोद शर्मा और अन्य को नियुक्त किया गया था

सहायक शिक्षकों का विधिवत योग्यता होना। 09.04.1970 पर,

जिला विद्यालय निरीक्षक (देहरादून) ने अनुमति दी

कक्षा I से VIII तक चलाने के लिए प्रबंधन। के निदेशक

शिक्षा ने इन शिक्षकों को 1978 के अधिनियम के तहत नहीं लाया।

सहायक शिक्षक विनोद शर्मा और अन्य ने एक रिट दायर की। भुगतान के लिए निर्देश की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका

1978 के अधिनियम के तहत उन्हें वेतन। राज्य के पदाधिकारी,

दूसरी ओर, 1975 के नियमों के नियम 10 पर भरोसा किया गया, जो

शिक्षकों और कर्मचारियों को दिया जाने वाला महँगाई भत्ता समान योग्यता रखने वाले बोर्ड का। उच्च न्यायालय ने

29.08.1991 पर रिट याचिका की अनुमति दी और राज्य को निर्देश दिया

रिट याचिकाकर्ताओं को प्रावधानों के तहत लाने के लिए पदाधिकारी

1978 के अधिनियम के तहत और तदनुसार उनके वेतन का भुगतान करें।

यू. पी. राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

उत्तर प्रदेश राज्य ने इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की

उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश, जिसे खारिज कर दिया गया था

इस न्यायालय द्वारा 10.05.1993 पर। पुनरीक्षण याचिका भी थी

इस न्यायालय द्वारा 17.09.1993 पर खारिज कर दिया गया। यहाँ पहला समाप्त हुआ

मुकदमेबाजी का दौर। चूंकि भुगतान के लिए कोई प्रार्थना नहीं थी

वेतन का बकाया, उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट आदेश पारित नहीं किया गया था

न्यायालय या इस न्यायालय और उत्तर प्रदेश राज्य ने भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया

01.07.1975 से प्रभावी वेतन। पीड़ित सहायक

शिक्षकों ने कई अभ्यावेदन देने के बाद दायर किया। एक और

बकाया भुगतान के लिए विशिष्ट निर्देश के लिए रिट याचिका

01.07.1975 के बाद से वेतन। उस मामले का निपटारा किया गया था

रिट याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान करने के निर्देश के साथ उच्च न्यायालय

29.08.1991 से प्रभावी। यह आदेश आया था कि इस न्यायालय में चुनौती दी जाए। तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया

1975 के नियमों के प्रावधान, विशेष रूप से की परिभाषाएँ

" जूनियर बेसिक स्कूल "और" मान्यता प्राप्त स्कूल "। होने के नाते

राज्य की ओर से दिए गए तर्कों के संबंध में कि

1978 का अधिनियम प्राथमिक धाराओं पर लागू नहीं था, अर्थात,

जूनियर बेसिक स्कूल और केवल जूनियर हाई के लिए आवेदन किया

स्कूलों, पीठ ने उच्च न्यायालय के पहले के फैसले का उल्लेख किया न्यायालय दिनांकित 29.08.1991 जिसने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि हालांकि

रिट याचिकाकर्ता प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे थे, वे

एक संस्थान में काम कर रहे थे जो एक जूनियर हाई स्कूल था

और वे सभी जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक थे जो चलता था

पहली से आठवीं तक की कक्षाएँ, जिन्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा था,

जो एक इकाई का गठन करती थी और अलग-अलग इकाइयाँ नहीं थीं। द.

विनोद शर्मा 1 मामले में फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है - इस प्रकार है:

" हालांकि, उपरोक्त जूनियर हाई स्कूल का भुगतान

वेतन अधिनियम, 1978 1 से 5 तक प्रभावी हुआ।

1979 धारा के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर 1 (3) . इस अधिनियम को बार-बार हटाने के लिए लाया गया था।

शिकायत है कि शिक्षकों और गैर-शिक्षकों का वेतन

सहायता प्राप्त गैर-सरकारी जूनियर हाई स्कूलों के कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2014] 13 एस सी आर।

समय पर वितरित नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप इसके लिए कठिनाइयाँ होती हैं कर्मचारी। उपरोक्त निर्णय दिनांकित 29-8-1991 इस अधिनियम का उल्लेख करता है। उत्तर प्रदेश के प्रत्यर्थी राज्य के लिए तर्क यह है कि यह प्राथमिक पर लागू नहीं होता है खंड, अर्थात्, कक्षा I से कक्षा V तक लेकिन केवल छठी से सातवीं कक्षा। अंततः उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्यर्थियों को अपीलार्थियों को उक्त अधिनियम के तहत लाने के लिए, जिसका अर्थ है 1978 के अधिनियम के तहत, और वेतन का भुगतान करें। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। द ऑपरेटिव उक्त आदेश का एक हिस्सा भी नीचे उद्धृत किया गया है:

" उत्तरदाताओं को एक अधिदेश द्वारा लाने के लिए निर्देशित किया जाता है के भुगतान के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ताओं वेतन अधिनियम और प्रावधानों के अनुसार उनके वेतन का भुगतान करें उक्त अधिनियम का "।

ऐसा नहीं है कि अपीलार्थी भुगतान के हकदार नहीं हैं। किसी भी वेतन से। वे हैं, लेकिन उन्हें नीचे लाने से पहले उक्त अधिनियम यह दायित्व केवल मान्यता प्राप्त पर है 1975 के नियमों के उपरोक्त नियम 10 के तहत स्कूल। लेकिन उक्त उच्च न्यायालय के फैसले से उत्तरदाताओं उन्हें वेतन के भुगतान के तहत लाने के लिए बाध्य थे तदनुसार कार्य करें और उनके वेतन का भुगतान करें। ऐसा नहीं हो सकता है। राज्य द्वारा अस्वीकार किया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं किया गया।

इस संबंध में।

राज्य की आपत्ति पर आते हुए, निवेदन यह है कि

वे केवल उक्त के तहत वेतन के भुगतान के हकदार हैं। 11-2-1993 के बाद से अधिनियम, उस तारीख को सरकार

उपरोक्त, अपीलार्थियों और अपीलार्थियों के बीच राज्य सहित उत्तरदाताओं का मामला बन गया है

उपरोक्त उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29-8 द्वारा अंतिम

1991. उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध, एस. एल. पी.

राज्य की याचिका खारिज कर दी गई थी; यहाँ तक कि समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई थी अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, अन्यथा भी राज्य में यू. पी. का कोई राज्य नहीं है।

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

दिनांकित विवादित फैसले के खिलाफ अपील में आएं

7-10-1996 , इसलिए यह इसे चुनौती नहीं दे सकता है। अपील करें।

विवादित क्रम पर लौटते हुए, हम पाते हैं, इसके बावजूद

कई अभ्यावेदन, कि उत्तरदाताओं ने नहीं किया

वेतन भुगतान अधिनियम के तहत उन्हें भुगतान करने का आदेश दिया गया कम से कम उच्च न्यायालय के पहले के फैसले और आदेश के बाद से

दिनांकित 29-8-1991।

अपीलार्थी विवादित आदेश से संतुष्ट नहीं थे,

जैसा कि उन्होंने 1975 से अपने वेतन का दावा किया जब

उपरोक्त 1975 का नियम लागू हुआ। विवाद यह है कि

पहले के उच्च न्यायालय के आदेश की भावना से भुगतान करना था

उस तारीख को। यह जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के रूप में था

तब से, इसलिए प्राथमिक वर्ग के शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते हैं

एक ही स्कूल में होने के कारण इस अधिकार से वंचित किया जाए। अन्य में

शब्द, उसी तारीख से भुगतान करने के लिए जो भुगतान किया गया था जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक। हम इसमें ताकत पाते हैं।

प्रस्तुत करना। जब अपीलार्थियों की शिकायत थी

उन्हें समानता में लाने के लिए पहली रिट याचिका में स्वीकार किया गया

जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ, भुगतान

1991 तथ्यों पर सही नहीं माना जा सकता है

इस मामले में। लेकिन अपीलार्थियों के दावे पर विचार करते हुए, वे किसी भी मामले में भुगतान किए जाने के हकदार नहीं हो सकते हैं

इसका पहला निर्णय, जहां इनका भुगतान करने का स्पष्ट निर्देश है वेतन भुगतान अधिनियम के तहत अपीलकर्ता

एक ही संस्थान शिक्षकों का एक और समूह (जूनियर हाई) स्कूल) को इसके तहत भुगतान किया जा रहा है और संस्थान को किया जा रहा है

एक इकाई, उसी में शिक्षकों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है

प्राथमिक खंड। दूसरे शब्दों में, उन्हें भी भुगतान करना

उसी अधिनियम के तहत जूनियर हाई स्कूल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की तारीख से

[2014]

13 एस सी आर।

इस संस्थान में शिक्षकों को वेतन दिया जाता था। जैसा कि हमने रखा है

ऊपर भले ही राज्य के लिए कोई तर्क हो सकता है कानून में योग्यता, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह बन गया है

पार्टियों के बीच अंतिम अंतर। यह भी हमारे लिए लाया जाता है

ध्यान दें कि ऐसे शिक्षकों में से एक के. एम. हर्ष उनियाल, समान

अपीलार्थियों को, हालांकि वे पहली रिट याचिका में शामिल नहीं हुए थे

लेकिन उस मामले के निर्णय (1991) के आधार पर, एक दायर किया

1993 की रिट याचिका संख्या 11644 जिसकी अनुमति दी गई थी

8-12-1993 पर उच्च न्यायालय ने भुगतान करने के निर्देश के साथ

उत्तरदाता "।

7. विनोद शर्मा में उपरोक्त दृष्टिकोण की शुद्धता 1

मामले में हमारे द्वारा जाँच की आवश्यकता है। यह अनिवार्य रूप से शामिल है

इस पहलू पर विचार करना कि क्या शिक्षा का पृथक्करण जूनियर हाई स्कूल स्तर से प्राथमिक स्तर पर और

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा बोर्ड का गठन

में निर्दिष्ट कनिष्ठ बुनियादी विद्यालयों पर नियंत्रण रखने के लिए पाँचवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान के रूप में 1975 के नियम,

विनोद शर्मा 1 में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को गलत तरीके से प्रस्तुत करें

कानून।

8. श्री पी. पी. राव, राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील

यू. पी. प्रस्तुत करता है कि 1978 का अधिनियम निजी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है

गैर-सहायता प्राप्त स्कूल और जूनियर के प्राथमिक वर्ग के शिक्षक

बेसिक स्कूल उक्त अधिनियम के लाभ के हकदार नहीं हैं। द. प्रबंधन दोनों शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है

1975 के नियमों और 1978 के अधिनियम के अनुसार। वहाँ कोई नहीं है

जूनियर बेसिक में शिक्षकों को वेतन के भुगतान का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा विद्यालय। प्रत्यर्थी के संबंध में

No.10, रियाज़ जूनियर हाई स्कूल (कक्षा VI से VIII), सीखा

वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि गैर-सहायता प्राप्त प्राथमिक अनुभाग

(वर्ग I से V) यू. पी. राज्य पर अलग मान्यता प्राप्त करने के बाद।

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

28.02.1980 , यद्यपि "प्राथमिक खंड" के रूप में संदर्भित, शब्दों में 1975 के नियमों के नियम 2 (बी) में परिभाषा का एक जूनियर बेसिक है।

स्कूल। नियम 4 में प्रबंधन से पर्याप्त व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है

इसके लिए वित्तीय संसाधन और नियम 10 प्रबंधन की आवश्यकता है। वेतन और भत्तों का भुगतान करने का वचन देना

दोनों शिक्षकों के लिए निर्धारित समान पैमाना। संदर्भ में

1975 नियम, तथ्य यह है कि जूनियर बेसिक स्कूल द्वारा चलाया जाता है

उसी परिसर में जूनियर हाई स्कूल का प्रबंधन

कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि

विनोद शर्मा में पहला दौर, उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में

दिनांक 29.08.1991, किसी भी वैधानिक प्रावधान को स्वीकार किए बिना, अभिनिर्धारित किया कि संस्थान में पढ़ाए जाने वाले सभी वर्ग एक इकाई हैं

और शिक्षक एक प्रबंधन और एक प्रमुख के तहत काम करते हैं।

भेदभाव। उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम हो गया विशेष अनुमति याचिका और समीक्षा याचिका के बाद भाग लेते हैं

राज्य द्वारा दायर किए गए आवेदन खारिज कर दिए गए। यही कारण है कि विनोद शर्मा 1 मामले का दूसरा दौर, तीन-न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ ने पहले के गुण-दोषों पर गौर करने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय का आदेश और केवल किस तारीख से विचार किया गया

शिक्षक 1978 के अधिनियम के तहत वेतन के हकदार होंगे।

9. श्री पी. पी. राव, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि

संदर्भ आदेश, दोनों-न्यायाधीशों की पीठ ने ठीक ही अलग किया है विनोद में पहले दौर में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ

शर्मा 1 ने मामला दर्ज किया और कहा कि उच्च न्यायालय ने नहीं किया

इस बात की सराहना करें कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को अलग कर दिया गया है

जूनियर हाई स्कूल स्तर से और अलग से सौंपा गया

1972 के अधिनियम की धारा 3 और उसी बोर्ड ने प्रयोग किया जूनियर बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण और यह एक सचेत था

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के दो सेटों के बीच विधानमंडल द्वारा किया गया अंतर

[2014]

13 एस सी आर।

स्कूल और उन्हें दो अलग-अलग घटकों के रूप में मानते हैं। वह. प्रस्तुत करता है कि जिस राज्य ने कानून बनाए हैं, उसने हमेशा

एक ही नज़र से। उनका तर्क है कि यह मानते हुए कि दो वैधानिक प्रावधानों के लिए व्याख्याएं संभव हैं, एक

संदर्भ का, जो नियम निर्माता के समान है, यह नियम निर्माता को जारी रखने की अनुमति देना उचित होगा

अधिनियमों और नियमों को उनकी समझ के अनुसार लागू करना।

शुरुआत से।

10. श्री पी. पी. राव ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 2 का उल्लेख किया,

विशेष रूप से पैराग्राफ 61 (पृष्ठ 546), जिसमें यह

न्यायालय ने कहा कि अक्षमता की समस्या का समाधान

समान स्तर पर संस्थान स्थापित करने के लिए राज्यों का

निजी विद्यालयों के रूप में उत्कृष्टता उन राज्यों में निहित होगी जो इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं

उन संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए उनके कम संसाधन जो सक्षम हैं

उन्नीकृष्णन 3 के संदर्भ में, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करें कि राज्य के संसाधनों का उपयोग किया जाना है

उन बच्चों के लाभ के लिए जो पहुँच से वंचित हैं

शिक्षा या इसे वहन नहीं कर सकते। विशिष्ट एच. पी. राज्य

मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्वान

वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में निर्णय था

लागू नहीं होता क्योंकि यह एक अलग सवाल माना जाता है कि क्या

सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के शिक्षक इसके हकदार हैं -

संविधान का अनुच्छेद 21 ए और बच्चों को स्वतंत्रता का अधिकार और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 लागू हुआ।

2 टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य; [(2002) 8 एस. सी. सी. 481] 3 जे. पी. उन्नीकृष्णन बनाम। एपी राज्य; [(1993)। एससीसी 645] 4 एच. पी. राज्य बनाम। एच. पी. राज्य मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय प्रबंधन समिति;

[(1995) 4 एस. सी. सी. 507] यू. पी. राज्य बनाम

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2010, वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं हैं जो

यह पहले की अवधि से संबंधित है।

11. श्री सुनील गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अपीलार्थियों के लिए अभिव्यक्ति का वह अर्थ प्रस्तुत करता है

" 1978 के अधिनियम में आने वाले "जूनियर हाई स्कूल" को होना चाहिए 1978 के नियमों के संदर्भ में निर्धारित किए गए जो बनाए गए थे

1972 के अधिनियम के तहत न तो 1978 के अधिनियम और न ही 1972 के अधिनियम के बाद से

अधिनियम "जूनियर हाई स्कूल" को परिभाषित करता है। वह बहुत अधिक निर्भर करता है

कानून को निर्माण के सभी उद्देश्यों के लिए माना जाना चाहिए और दायित्व ठीक वैसे ही जैसे वे अधिनियम में थे, और होने वाले हैं

अधिनियम में निहित होने के समान प्रभाव, और न्यायिक रूप से होना चाहिए

निर्माण और दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए नोटिस किया गया (मैक्सवेल ' क़ानूनों की व्याख्या पर, 10 वीं संस्करण) . सीखा हुआ वरिष्ठ

वकील प्रस्तुत करता है कि व्याख्या का यह सिद्धांत स्वीकार किया जाता है बाबू राम 3 और विभा में इस न्यायालय द्वारा। वह प्रस्तुत करता है कि लेना

1972 के अधिनियम की धारा 4 (2) (बी) और 1978 के नियम मार्गदर्शक के रूप में

कारक, अभिव्यक्ति "जूनियर हाई स्कूल" ले जाएगा, के रूप में

1978 के अधिनियम की धारा 2 (जे) के अनुसार, जिसका अर्थ है "कक्षा VI से

VIII "और कक्षा I से V तक को बाहर रखा गया है।

12. वैकल्पिक रूप से, श्री सुनील गुप्ता का तर्क है कि एक

कानूनी सिद्धांत अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि जब एक अभिव्यक्ति में

एक बाद का क़ानून अस्पष्ट है, इसके अर्थ का पता लगाया जा सकता है

एक पूर्व कानून या वैधानिक में इसके उपयोग और/या अर्थ से

एक ही विषय वस्तु से संबंधित उपकरण। इस संबंध में, वह दो अंग्रेजी फैसलों, बारास और गल्लाघेर पर निर्भर करता है।

5 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। बाबू राम उपाध्याय; [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 751]

6 नगर महापलिका, कानपुर बनाम। विभा शुक्ला (श्रीमती) और अन्य; [(2007) 15 एस. सी. सी. 161]

7 1 बारास बनाम। एबरडीन स्टीम ट्रालिंग एंड फिशिंग कंपनी; [1933 सभी ईआर 52]

8 गलाघेर वी। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर-डे सेंट्स; [(2008) 4 सभी ईआर 640]

9 डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; [AIR 1961]

और डायमंड शुगर, सिरसिल्क में इस न्यायालय के तीन निर्णय

और शुद्ध 1 1। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करेगा कि उपयोग और अर्थ अभिव्यक्ति "जूनियर हाई स्कूल" के साथ पता लगाया जाना चाहिए

1972 के अधिनियम की धारा 4 (2) (बी) और 1972 के अधिनियम के नियम 2 (ई) का संदर्भ

1978 के नियम।

13. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि इसके बावजूद

व्यापक अभिव्यक्ति "बेसिक स्कूल" जिसमें कक्षा I से VIII तक शामिल हैं

उपलब्ध होने के कारण, कम से कम 1972 से, विधानमंडल ने नहीं चुना

1978 के अधिनियम में उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग करना। बल्कि, इसके विपरीत इसके साथ, विधानमंडल ने "जूनियर हाई" अभिव्यक्ति को चुना।

1978 के अधिनियम में स्कूल। विधायिका का इरादा, सीखा वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं, 1978 के अधिनियम को संकीर्ण पर लागू करना है

श्रेणी, अर्थात् केवल छठी से आठवीं तक और पहली से आठवीं तक के लिए नहीं। बुनियादी स्कूलों का वी।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील भी प्रस्तुत करते हैं कि पूरी तरह से

के दो सेटों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है

शिक्षक, (1) छठी से आठवीं कक्षा के शिक्षक और (2) कक्षा के शिक्षक।

वैधानिक प्रावधानों में कक्षा I से V, अर्थात्, 1975

एक ओर नियम और दूसरी ओर 1978 का नियम/1978 अधिनियम

दूसरा हाथ।

15. डॉ. एम. पी. राजू, प्रतिवादी संख्या के लिए विद्वान वकील। 1

9 तक, विद्वान वरिष्ठ औंसेल के तर्कों के जवाब में अपीलार्थियों के लिए, तर्क है कि "जूनियर बेसिक स्कूल" शब्द

इसका अर्थ है और इसमें कक्षा I से VIII तक शामिल हैं जहाँ भी कक्षा I से V तक वे उक्त विद्यालय का हिस्सा हैं। वह प्रस्तुत करता है कि एक प्रथम से आठवीं कक्षा को सहायता प्रदान करने का राज्य का दायित्व और उसी जूनियर के जूनियर बेसिक स्कूल अनुभाग का बहिष्कार सहायता से हाई स्कूल भेदभावपूर्ण और अस्वीकार्य है वर्गीकरण।

16. विद्वान वकील ने विनोद शर्मा 1 का उल्लेख किया, जिसमें यह आयोजित किया गया था: याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षा दे रहे होंगे

10 सिरसिल्क बनाम। वस्त्र समिति और अन्य; [1989 पूरक 1 एस. सी. सी. 168]
11 अध्यक्ष, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम। शुद्ध औद्योगिक कोक और रसायन लिमिटेड और अन्य; [(2007) 8 एस. सी. सी. 705] यू. पी. राज्य बनाम

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

कक्षाएँ लेकिन वे उस संस्थान में काम कर रहे थे जो जूनियर है

हाई स्कूल और वे जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक हैं

जो पहली से आठवीं तक की कक्षाएँ चलाती है। सभी वर्ग जो हैं

विद्यालय में पढ़ाया जाना एक इकाई है और वे हैं

अलग-अलग इकाइयाँ नहीं "। अनुच्छेद 21,41,45,46 और, संविधान के अनुच्छेद 21 ए और 51 ए (के) के बाद,

विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि राज्य का दायित्व है

(कक्षा I से VIII), 6 से 14 के छात्रों के लिए। वर्षों से।

17. उसके निवेदन के समर्थन में सीखा हुआ वकील कि

राज्य का दायित्व है कि वह बुनियादी सुविधाओं को अनुदान प्रदान करे

शिक्षा या बुनियादी स्कूलों (कक्षा I से VIII) ने काफी कुछ उद्धृत किया है।

इस न्यायालय के निर्णय। उनमें से कुछ उन्नीकृष्णन 3 हैं,

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 2, एच. पी. राज्य मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालय

प्रबंध समिति और माता तपेश्वरी 1 2.

18. विद्वान वकील डॉ. एम. पी. राजू भी प्रस्तुत करते हैं कि

जूनियर हाई स्कूल से कक्षा I से V को छोड़कर वर्गीकरण

सहायता के उद्देश्य के लिए भेदभावपूर्ण और बिना किसी भेदभाव के

उचित उद्देश्य या कोई तर्कसंगत सांठगांठ।

19. विद्वान वकील का तर्क है कि 1978 का अधिनियम

जूनियर हाई स्कूल को जूनियर को शामिल करने पर विचार करता है

बेसिक स्कूल, यानी कक्षा I से V तक, जहाँ भी

एक साथ जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए अग्रणी हैं। द. जिन विद्यालयों में जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल हैं

स्कूल या तो अलग से या एक साथ एक ही के अंतर्गत आते हैं।

बोर्ड, अर्थात, प्रावधानों के अनुसार बुनियादी शिक्षा बोर्ड

1972 का अधिनियम। कक्षाओं वाले स्कूलों को दी गई सहायता

VIII और उससे नीचे को वैधानिक योजना के तहत लाया गया था

1978 अधिनियम के माध्यम से वेतन का भुगतान। कक्षा I को छोड़कर

V के लिए जो एक ही स्कूल में बुनियादी स्कूलों का हिस्सा हैं या

12 यू. पी. राज्य बनाम प्रबंधन समिति, माता तपेश्वरी; [(2010)

1978 के अधिनियम के संचालन से संस्था होगी

अतार्किक। इस प्रकार, विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि लिया गया दृष्टिकोण

विनोद शर्मा में 1 सही दृष्टिकोण है।

20. विद्वान वरिष्ठ के तर्कों को ध्यान में रखते हुए

पक्षों की ओर से पेश वकील और वकील, हम सोचते हैं कि पहले दिए गए तर्कों पर उचित विचार करने के लिए

हम, एक के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना उचित है

कुछ वैधानिक अधिनियम और उनके द्वारा बनाए गए नियम

समय-समय पर सरकार।

21. 1921 में, यू. पी. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

(संक्षेप में "1921 अधिनियम") की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा (संक्षेप में, "बोर्ड")

जिसने विनियमन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लिया और

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्रणाली का पर्यवेक्षण करना

उत्तर प्रदेश में शिक्षा और उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करें।

1921 के अधिनियम की धारा 2 (ए), जैसा कि 1975 में संशोधित किया गया था, परिभाषित करती है

" बोर्ड "और धारा 2 (बी)" संस्थान "को परिभाषित करती है। धारा 2 (ए) में, " बोर्ड "का अर्थ है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड।

शिक्षा. धारा 2 (बी) में "संस्था" अभिव्यक्ति का अर्थ है

एक मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च माध्यमिक विद्यालय

या हाई स्कूल, और शामिल है, जहां संदर्भ की आवश्यकता है, एक

एक संस्था का हिस्सा। धारा 7 की शक्तियों से संबंधित है

बोर्ड। धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत, एक शक्ति

बोर्ड को अंत में परीक्षा आयोजित करने का अधिकार दिया गया है

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम।

22. उत्तर प्रदेश की शैक्षिक संहिता (संशोधित 1958)

संस्करण) जिसे अभिलेख में रखा गया है, महत्वपूर्ण है।

पैरा 1 के खंड (x) और (XXVI) "संस्थान" और "विद्यालय" को परिभाषित करते हैं,

क्रमशः इस प्रकार है:

" 1 (x) संस्थान का अर्थ है एक शैक्षणिक संस्थान। इस तरह

संस्थानों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है।

(क) मान्यता प्राप्त संस्थान का अर्थ है एक संस्था जो

यू. पी. v. के निर्धारित या राज्य निर्देश का पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

या एक विश्वविद्यालय, और इनमें से एक या अधिक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, दक्षता के मामले में।

ऐसी संस्था समय-समय पर निरीक्षण के लिए खुली है।

विभाग का कोई अधिकारी या अधिकारी और उसके छात्र

सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रवेश के लिए पात्र हैं

विभाग, या मध्यवर्ती बोर्ड द्वारा संचालित, या एक विश्वविद्यालय;

(ख) गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान का अर्थ है ऐसी संस्था जो

मान्यता प्राप्त की उपरोक्त परिभाषा के तहत नहीं आता है संस्थान;

(XXVI) विद्यालय का अर्थ है एक मान्यता प्राप्त संस्थान जो निम्नलिखित है:

विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या

मध्यवर्ती बोर्ड। कई प्रकार के विद्यालय हैं इस प्रकार है:

(क) नर्सरी स्कूल का अर्थ है एक ऐसा स्कूल जहां के बच्चे -

पूर्व-मूल अवस्था, अर्थात लगभग तीन से छह वर्ष की आयु तक

सिखाया जाता है,

(ख) जूनियर बेसिक स्कूल का अर्थ है एक स्कूल शिक्षण।

आम तौर पर 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे कक्षा I से V (अर्थात प्राथमिक अनुभाग),

(ग) सीनियर बेसिक स्कूल या जूनियर हाई स्कूल का अर्थ है

या तो एक स्कूल जो छात्रों को जूनियर हाई के लिए तैयार कर रहा है विभाग या विद्यालय की विद्यालय परीक्षा

कक्षा I से VIII या VI से VIII (मध्य खंड) को पढ़ाना,

नोट-बेसिक स्कूलों में सीनियर या जूनियर बेसिक दोनों शामिल हैं।

स्कूलों के साथ-साथ कक्षा I से VIII तक के एकल स्कूल।

((घ) उच्च माध्यमिक विद्यालय का अर्थ है ऐसा विद्यालय जो

निम्न वर्गों के साथ या उनके बिना कक्षा IX और

X और/या XI और XII और छात्रों को उच्च के लिए तैयार करता है

इंटरमीडिएट बोर्ड या विश्वविद्यालय की स्कूल और/या इंटरमीडिएट परीक्षाएँ;

:

13 एस सी आर।

23. 1971 का अधिनियम भुगतान को विनियमित करने के लिए बनाया गया था।

उच्च विद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन

और राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले इंटरमीडिएट कॉलेज

और उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना। धारा 2 (बी)

1971 के अधिनियम में "संस्थान" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है मान्यता प्राप्त।

से रखरखाव अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था

राज्य सरकार और इसमें एक संस्कृत महाविद्यालय शामिल है।

या एक संस्कृत विद्यालय जो रखरखाव अनुदान प्राप्त कर रहा है

राज्य सरकार। धारा 2 इस प्रकार की अभिव्यक्तियों को भी परिभाषित करती है -

"प्रबंधन", "शिक्षक", "कर्मचारी" और "वेतन" के रूप में। द.

अवशिष्ट परिभाषा खंड, अर्थात।, 1971 के अधिनियम की धारा 2 (एच),

यह कहता है कि 1921 के अधिनियम में अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ यदि उनके तहत परिभाषित नहीं किया गया है तो उन्हें दिया गया अर्थ है

एक्ट करें। 1971 के अधिनियम की धारा 5 में प्रक्रिया का प्रावधान है - कुछ संस्थानों के मामले में वेतन का भुगतान।

24. 1972 के अधिनियम में एक की स्थापना का प्रावधान है

बुनियादी शिक्षा बोर्ड और उससे जुड़े मामलों के लिए। उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि

अब तक प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिला पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरपालिका बोर्डों के साथ परिषद और

शहरी क्षेत्रों में महापलिकास। शिक्षा का प्रशासन

इस स्तर पर स्थानीय निकायों द्वारा संतोषजनक नहीं था, और यह था दिन-ब-दिन बिगड़ता जा रहा है। जनता की मांग थी कि

सरकार सुधार के लिए तत्काल कदम उठाएगी

इस स्तर पर शिक्षा। अतः पुनर्गठन, सुधार और

प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, यह आवश्यक हो गया

राज्य सरकार अपना नियंत्रण अपने हाथों में ले। यह.

आगे रिकॉर्ड करता है कि प्राथमिक और कनिष्ठ को मजबूत करने के लिए

उच्च विद्यालय और उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, सरकार

अपने नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी लेने जा रहा था और

प्रबंधन। सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की दृष्टि से

संविधान के अनुच्छेद 45 का उद्देश्य, सरकार

से प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है

उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा बोर्ड के लिए स्थानीय निकाय।

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

" धारा 2 (बी) में परिभाषित बुनियादी शिक्षा का अर्थ है शिक्षा। हाई स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों में दी जाने वाली आठवीं कक्षा तक

स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज, और अभिव्यक्ति "बुनियादी"

स्कूलों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।

25. 1972 के अधिनियम की धारा 4 में कार्यों का प्रावधान है

बोर्ड से। बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, संगठित करना, समन्वय करना है

और बुनियादी शिक्षा प्रदान करने को नियंत्रित करना। अंदर आने पर

अधिनियम का बल, प्रबंधन, पर्यवेक्षण और

उपखंड (सी. सी.) या (डी.) के तहत बुनियादी विद्यालयों पर नियंत्रण

धारा (2), जो नियत दिन से पहले स्थानीय की थी

निकाय, ऐसे विद्यालयों के संबंध में बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था।

26. धारा की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग

19 1972 के अधिनियम के तहत 1975 के नियम बनाए गए थे। 1975 में

नियम 2 (बी) के तहत, अभिव्यक्ति "जूनियर बेसिक स्कूल"

परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है उच्च विद्यालयों के अलावा एक संस्थान या इंटरमीडिएट कॉलेज जो कक्षा V तक शिक्षा प्रदान करते हैं।

नियम 2 (सी) में "मान्यता प्राप्त विद्यालय" का अर्थ है - जूनियर बेसिक स्कूल, जो किसी संस्थान से संबंधित नहीं है या

बोर्ड या किसी मान्यता प्राप्त स्थानीय निकाय द्वारा पूरी तरह से बनाए रखा गया

इन नियमों के प्रारंभ से पहले बोर्ड द्वारा

पहली से पांचवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने के लिए नियम 4 में प्रावधान है कि

प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएगा।

ऐसे विद्यालय के प्रबंधन द्वारा इसके लिए उपलब्ध कराया जाए

कुशलता से काम करने और पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

जिन विषयों के संबंध में ऐसे विद्यालय हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए बोर्ड पहचाना जाता है। नियम 7 में प्रावधान है कि प्रावधानों के अधीन

शिक्षा संहिता के पैरा 106 से 114 तक, जहाँ तक वे हैं

लागू होने पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

स्कूल की सूची में छात्रों की संख्या का 25 प्रतिशत

इस तरह के स्कूल।

13 एस सी आर।

27. 1978 के नियम राज्यपाल द्वारा बनाए गए थे

धारा की उप-धारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य

19 1972 का अधिनियम। ये नियम ई. एफ. से लागू हुए।

13.02.1978 . नियम 2 के खंड (सी) और (ई) "बोर्ड" को परिभाषित करते हैं और

" जूनियर हाई स्कूल "।

" बोर्ड "का अर्थ है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ बेसिक

1972 के अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित शिक्षा।

" जूनियर हाई स्कूल "का अर्थ है इसके अलावा कोई अन्य संस्थान।

लड़कों को शिक्षा प्रदान करने वाले हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज

या छठी से आठवीं कक्षा तक की लड़कियां या दोनों (समावेशी)।

28. 1978 का अधिनियम उत्तर प्रदेश द्वारा अधिनियमित किया गया।

प्रदेश विधानमंडल को वेतन के भुगतान को विनियमित करने के लिए

प्राप्त करने वाले जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी

राज्य निधि से सहायता और संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करना।

इसके साथ। यह अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. 01.05.1979 से लागू हुआ। खंड

(ख), खंड (ई), खंड (एच) और खंड (आई) "शिक्षा" को परिभाषित करते हैं।

अधिकारी "," संस्थान "," शिक्षक "और" वेतन ", क्रमशः।

" शिक्षा अधिकारी "का अर्थ है जिला बुनियादी शिक्षा।

1972 के अधिनियम के तहत और लड़कियों के संबंध में नियुक्त अधिकारी

प्रत्येक मामले में राज्य द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी शामिल है। सरकार के सभी या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए

इस अधिनियम के तहत शिक्षा अधिकारी।

" "संस्थान" से कोई मान्यता प्राप्त कनिष्ठ उच्च विद्यालय अभिप्रेत है।

जिस समय राज्य से रखरखाव अनुदान प्राप्त हो रहा है

सरकार।

" किसी संस्थान के शिक्षक का अर्थ है प्रधानाध्यापक या अन्य।

शिक्षक जिनके संबंध में रोजगार रखरखाव अनुदान

संस्थान को राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

" शिक्षक या कर्मचारी के वेतन का अर्थ है कुल राशि।

महँगाई या किसी अन्य भत्ते सहित परिलब्धियों का, यू. पी. राज्य v.

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

उस समय के लिए उसके लिए स्वीकृत दर पर देय

रखरखाव अनुदान के भुगतान का उद्देश्य।

परिभाषा खंड में धारा 2 का खंड (जे) कहता है कि

1972 के अधिनियम में परिभाषित अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ, नहीं

1978 के अधिनियम में परिभाषित, के लिए निर्धारित अर्थ होंगे

उस अधिनियम में।

29. 1978 के अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि राज्य

और किसी भी अवधि के संबंध में देय प्रत्येक संस्थान के कर्मचारी नियत दिन के बाद।

30. धारा 13-ए इस संबंध में अस्थायी प्रावधान करती है।

कुछ उन्नत संस्थानों का। इसमें लिखा है:

" 13 - ए. कुछ के संबंध में अस्थायी प्रावधान

उन्नत संस्थान। (1) इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

इस अधिनियम के प्रावधान, उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे,

एक संस्थान जिसे उच्च विद्यालय में उन्नत किया गया है या

मध्यवर्ती मानक और ऐसे शिक्षकों और अन्य लोगों के लिए

उनके कर्मचारी जिनके रोजगार के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा रखरखाव अनुदान का भुगतान किया जाता है

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए संदर्भ छात्र जहाँ कहीं भी वे धारा 5 में होते हैं,

तक कक्षाओं के छात्रों के संदर्भ के रूप में माना जाता है

केवल जूनियर हाई स्कूल स्तर "।

31. धारा 15 राज्य सरकार को अधिकार देती है -

अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना।

प्रावधान में कहा गया है:

" 15. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। — (1) अगर कोई परेशानी है। इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में उत्पन्न होता है या

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के कारण, राज्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2014] 13 एस. सी. आर.

सरकार, अवसर की आवश्यकता के अनुसार, अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या परिणामी प्रावधान करें

किसी भी अनुकूलन या संशोधन के लिए प्रावधानों सहित

इस अधिनियम या उत्तर प्रदेश मूल का प्रावधान

शिक्षा अधिनियम, 1972 या उसके अधीन बनाए गए नियम, लेकिन पदार्थ को प्रभावित नहीं करना, जैसा कि यह आवश्यक समझता है या

(2) इसके बाद उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। से तीन साल की अवधि की समाप्ति

नियत दिन।

(3) उप-धारा (1) के तहत किया गया प्रत्येक आदेश रखा जाएगा,

जितनी जल्दी हो सके राज्य के दोनों सदनों के समक्ष

विधायिका "।

32. धारा 17 राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार देती है

इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम।

33. जैसा कि देखा जा सकता है, 1978 का अधिनियम राज्य को ऐसा बनाता है

शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए सरकार उत्तरदायी है और प्राप्त करने वाले प्रत्येक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के कर्मचारी

हाई स्कूल को 1978 के अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। हमे करना है। "जूनियर हाई स्कूल" अभिव्यक्ति का अर्थ निर्धारित करें

1978 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए। लेकिन हम ऐसा करने से पहले, ए

सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के दायित्व के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी

बुनियादी शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान

6 से 14 वर्ष के छात्रों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

86 वीं तारीख तक संविधान में अनुच्छेद 21-ए को शामिल करने से पहले

संशोधन अधिनियम, 2002 जिसे मंजूरी मिली

12.12.2002 , इस न्यायालय ने उन्नीकृष्णन 3 में कहा कि

14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मौलिक अधिकार है -

मुफ्त शिक्षा।

34. अनुच्छेद 45 जो विचाराधीन था

उन्नीकृष्णन 3 में लिखा है कि "राज्य यू. पी. बनाम के बारे में बताने का प्रयास करेगा।

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

शुरुआत से 10 साल की अवधि के भीतर

संविधान सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए है।

जब तक वे 14 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते।

35. रिपोर्ट के अनुच्छेद 172 में, संविधान

च ने उन्नीकृष्णन 3 में कहा:

" 172. सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार जब तक कि वे चौदह वर्ष की आयु पूरी करना (कला। 45)। यह है।

उल्लेखनीय है कि भाग IV के कई लेखों में से केवल

अनुच्छेद 45 एक समय सीमा की बात करता है; कोई अन्य अनुच्छेद ऐसा नहीं करता है।

क्या इसका कोई महत्व नहीं है? इसके बाद भी क्या यह केवल एक पवित्र इच्छा है?

44 संविधान के वर्षों? क्या राज्य उक्त का उल्लंघन कर सकता है?

44 वर्षों के बाद भी इस आधार पर निर्देश कि लेख

केवल इसे "प्रदान करने का प्रयास" करने के लिए कहता है

और आगे इस आधार पर कि उक्त लेख नहीं है

अनुच्छेद 37 में घोषणा के आधार पर प्रवर्तनीय। करता है। 44 साल नहीं-चार गुना से अधिक

भारत में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपलब्ध निधि द्वारा इंगित प्राथमिकताओं के व्युत्क्रम का खुलासा करता है

संविधान। संविधान ने एक दुर्घटना पर विचार किया

इसे प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई योजना

अनुच्छेद 45 में निर्धारित लक्ष्य। यह ध्यान देने योग्य है कि

अनुच्छेद 45 "इसकी आर्थिक सीमाओं" की बात नहीं करता है।

क्षमता और विकास "जैसा कि अनुच्छेद 41 करता है, आलिया शिक्षा के अधिकार की बात करती है। वास्तव में क्या है

हुआ है-अधिक पैसा खर्च किया जाता है और अधिक ध्यान दिया जाता है

की तुलना में उच्च शिक्षा के लिए निर्देशित है-और कीमत पर

की-प्राथमिक शिक्षा। (प्राथमिक शिक्षा से हमारा मतलब है

शिक्षा, जो एक सामान्य बच्चा समय से प्राप्त करता है

वह 14 वर्ष की आयु पूरी करता है।) उपेक्षा अधिक होती है

ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2014] 13 एस सी आर।

अनुच्छेद 46 में निर्दिष्ट। हम स्पष्ट करते हैं, हम नहीं चाहते हैं सरकार के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करें-हम केवल

द्वारा प्रकट संवैधानिक नीति पर जोर देना अनुच्छेद 45,46 और 41। निश्चय ही इन लोगों की बुद्धिमत्ता

संवैधानिक प्रावधान सवाल से परे हैं। यह

प्राथमिकताओं के व्युत्क्रम पर टिप्पणी की गई है

शिक्षाविदों और अर्थशास्त्रियों दोनों के लिए प्रतिकूल।

फिर, पैराग्राफ 175 में, अदालत ने कहाः " 175. जो भी हो, हमें यह कहना होगा कि कम से कम अब

राज्य को अनुच्छेद 45 के आदेश का सम्मान करना चाहिए। इसे होना ही चाहिए।

एक वास्तविकता बनाई जाए-कम से कम अभी। वास्तव में, राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि अनुच्छेद का वादा

45 इस सदी के अंत से पहले इसे छुड़ा लिया जाएगा। बनो।

कि जैसा भी हो, हम मानते हैं कि एक बच्चे (नागरिक) के पास है

14 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार बरसों "।

उन्नीकृष्णन 3 के अनुच्छेद 176 में न्यायालय ने कहा कि

डब्ल्यूएसः

" 176. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह दायित्व

केवल राज्य विद्यालयों के माध्यम से ही प्रदर्शन किया जा सकता है। यह हो सकता है।

अनुमति देकर, पहचान कर और सहायता करके भी किया जाए

स्वैच्छिक गैर-सरकारी संगठन, जो हैं

बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार। यह करता है।

इसका यह भी मतलब नहीं है कि गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल ऐसा नहीं कर सकते हैं जारी रखें। वास्तव में, वे भी एक भूमिका निभा सकते हैं।

वे जनसंख्या के उस वर्ग की मांग को पूरा करते हैं जो

हो सकता है कि वे अपने बच्चों को राज्य में पढ़ाना न चाहें।

विद्यालय। उन्हें अनिवार्य रूप से शुल्क लेना पड़ता है

ऐसे विद्यालयों के बारे में या उस मामले के लिए कुछ भी कहें 'पेशेवर' को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थान

महाविद्यालय '। यह चर्चा वास्तव में आवश्यक है मोहिनी जैन बनाम में प्रतिपादित सिद्धांतों का विवरण।

यू. पी. राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

इन रिट याचिकाओं में उन सिद्धांतों के खिलाफ आरोप लगाया गया है।
36. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन 2 में, ग्यारह-न्यायाधीश

संविधान पीठ ने उन्नीकृष्णन 3 के विचार को मंजूरी दी उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा एक

मौलिक अधिकार। प्रश्न 9 और उसका उत्तर (पृ. 590 में से

रिपोर्ट) नीचे पढ़ा गया है:

" प्र. 9. क्या उन्नी में इस न्यायालय का निर्णय

कृष्णन, जे. पी. वी. ए. पी. की स्थिति (सिवाय इसके कि जहां यह मानती है कि

प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है) और इसके तहत बनाई गई योजना पर पुनर्विचार की आवश्यकता है /

संशोधन और यदि हाँ, तो क्या?

उ. उन्नी कृष्णन में इस न्यायालय द्वारा बनाई गई योजना

मामला और उसी को लागू करने का निर्देश, सिवाय इसके

जहाँ यह माना जाता है कि प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक शिक्षा है।

सही है, असंवैधानिक है। लेकिन सिद्धांत यह है कि

कैपिटेशन शुल्क या मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए

सही है। विस्तार लागत को पूरा करने के लिए उचित अधिशेष

हालाँकि, सुविधाओं में वृद्धि नहीं होती है। मुनाफाखोरी की राशि "।

37. पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का बयान

उन्नीकृष्णन 3 में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार है। एच. पी. राज्य मान्यता प्राप्त उच्च विद्यालयों के प्रबंधन में प्रतिध्वनित होता है

समिति 1 भी। पैराग्राफ में तीन-न्यायाधीशों की पीठ

16 और 17 (pgs. 514-515 रिपोर्ट) ने दोहराया कि

मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को संवैधानिक जनादेश

14 वर्ष की आयु तक के बच्चे। तीन-न्यायाधीशों की पीठ

उन्होंने कहाः

" 16. राज्य के लिए संवैधानिक जनादेश, जैसा कि बरकरार रखा गया है

इस अदालत द्वारा उन्नी कृष्णन मामले में-मुफ्त प्रदान करने के लिए

चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा

जमीन पर भटकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है आर्थिक क्षमता या वित्तीय अक्षमता की कमी।

13 एस सी आर।

17. यह सही समय है कि राज्य को इसे स्वीकार करना चाहिए।

बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी

चौदह वर्ष की आयु तक। शिक्षा का अधिकार समान है।

उम्र से ऊपर के बच्चों के लिए गारंटी

चौदह, लेकिन वे इसे तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक कि

आर्थिक क्षमता और राज्य अनुमतियों का विकास

उसी का प्रवर्तन। राज्य को प्रयास करना चाहिए

बजट आवंटन की समीक्षा और वृद्धि करना

प्रमुख 'शिक्षा'। भारत संघ को भी विचार करना चाहिए

निधियों के आवंटन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए

" शिक्षा "सकल राष्ट्रीय उत्पाद से बाहर"।

38. उपरोक्त संवैधानिक दर्शन के साथ, आइए हम "जूनियर हाई स्कूल" अभिव्यक्ति का अर्थ निर्धारित करें 1978 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए।

39. इस बात पर ज्यादा बहस नहीं है कि छात्रों माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों को धारा 3 में वर्गीकृत किया गया है शैक्षिक संहिता (संशोधित 1958 संस्करण) इस प्रकार है:

(क) पूर्व-मूल अवस्था

...... नर्सरी शिक्षा

(ख) जूनियर बेसिक (प्राथमिक) चरण। कक्षा I से V तक

(ग) सीनियर बेसिक (जूनियर हाई स्कूल)। छठी से आठवीं कक्षा

स्टेज

((घ) उच्चतर माध्यमिक स्तर:

1. हाई स्कूल स्टेज

...... नौवीं और दसवीं कक्षा

II. मध्यवर्ती चरण

...... ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा

40. अपीलार्थियों की ओर से भारी निर्भरता रखी जाती है।

1978 के नियमों में "जूनियर हाई स्कूल" की परिभाषा पर।

क्या 1978 के नियमों में "जूनियर हाई स्कूल" की परिभाषा है? 1978 के अधिनियम में होने वाली एक ही अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना? हम.

ऐसा मत सोचिए। नियम में "जूनियर हाई स्कूल" की परिभाषा।

2 (ई) 1978 के नियमों को 1978 के अधिनियम में भी शामिल नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से या निहित रूप से। व्याख्या का सिद्धांत कि यू. पी. का एक राज्य v.

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

कानून में होने वाली अभिव्यक्ति को ही निर्धारित किया जाना है। जाहिर है कि बनाए गए नियम की मदद से ऐसा नहीं किया जा सकता है।

एक अलग कानून के तहत।

41. 1978 अधिनियम की धारा 2 (जे) में कहा गया है कि शब्द और

1972 के अधिनियम में परिभाषित अभिव्यक्तियाँ और इनमें परिभाषित नहीं

अधिनियम का वही अर्थ होगा जो 1972 के अधिनियम में उन्हें सौंपा गया है।

गुप्ता, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अनुरोध किया कि बनाए गए कानूनों की व्याख्या के सिद्धांत का आह्वान करें

एक कानून के तहत निर्माण के सभी उद्देश्यों के लिए माना जाना चाहिए

और दायित्व जैसे कि वे अधिनियम में थे, और होने वाले हैं

अधिनियम में निहित होने के समान प्रभाव, और होने वाले हैं

निर्माण और दायित्व के सभी उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से देखा गया।

इस सिद्धांत का आह्वान गलत है। सबसे पहले, क्योंकि

हम एक अभिव्यक्ति के निर्माण से संबंधित नहीं हैं

1972 के अधिनियम में जिसके तहत 1978 के नियम बनाए गए हैं।

दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो नियम बनाता हो। एक अलग और विशिष्ट कानून के तहत बनाया गया माना जाना चाहिए

निर्माण के उद्देश्य जैसे कि वे अधिनियम का हिस्सा थे। में।

निर्माण के उद्देश्यों के लिए न्यायिक रूप से नोटिस नहीं किया जा सकता है और 1978 के अधिनियम का दायित्व।

42. हम श्री के निवेदन से भी सहमत नहीं हैं।

सुनील गुप्ता ने कहा कि चूंकि "जूनियर हाई स्कूल" अभिव्यक्ति है

1978 के अधिनियम में परिभाषित नहीं है, इसके अर्थ का पता लगाया जा सकता है

1978 के नियमों से इस सिद्धांत को लागू करते हुए कि जब

बाद के क़ानून में अभिव्यक्ति अस्पष्ट है, इसका अर्थ हो सकता है

पूर्व कानून में इसके उपयोग और/या अर्थ से पता लगाया गया है या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के लिए एक ही विषय वस्तु से संबंधित वैधानिक साधन

[2014]
13 एस सी आर।

बहुत अधिक चुनौती नहीं है। सवाल इसकी प्रयोज्यता का है। वर्तमान मामले में। 1978 के नियम राज्यपाल द्वारा बनाए गए हैं।

1972 के अधिनियम के तहत, जो के पहलू से संबंधित नहीं है

शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल। राज्य विधानमंडल ने एक

1978 के नियमों में "जूनियर हाई स्कूल" की परिभाषा है "जूनियर हाई स्कूल" अभिव्यक्ति के दायरे को समाप्त नहीं करता है।

इसके अलावा, एक पूर्व रूफ को एक अर्थ लगाने के लिए सहायता में नहीं लिया जा सकता है

बाद का अधिनियम।

43. यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मान्यता प्राप्त जूनियर

उच्च विद्यालय तीन प्रकार के हो सकते हैं: (एक) कक्षा I से लेकर

आठवीं, यानी कक्षा I से V (जूनियर बेसिक स्कूल) और इसी तरह

कक्षा VI से VIII (सीनियर बेसिक स्कूल), (दो) एक स्कूल के रूप में

ऊपर और उच्च विद्यालय या मध्यवर्ती मानक में उन्नत

और (तीन) कक्षा छठी से आठवीं (वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय) शुरू में कोई जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा I से V) इसका हिस्सा नहीं है

स्कूल ने कहा।

44. जूनियर हाई की पहली दो श्रेणियों के संबंध में

विद्यालयों में 1978 के अधिनियम की धारा 10 लागू होती है।

कोई कठिनाई पैदा न करें। बहस जो चारों ओर केंद्रित है

अपीलों के इस समूह में तीसरी श्रेणी के संबंध में है स्कूल जहाँ कक्षा I से V प्राप्त करने के बाद जोड़े जाते हैं

उन विद्यालयों को मान्यता जो छठी से आठवीं कक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त हैं। क्या शिक्षक ऐसे विद्यालयों में प्राथमिक वर्ग की कक्षा I से V तक के छात्र इस अधिकार के हकदार हैं -

1978 के अधिनियम की धारा 10 का लाभ विवादास्पद प्रश्न है।

जैसा कि देखा गया है, प्रदान करने के लिए राज्य का संवैधानिक दायित्व बच्चों की पूर्ण शिक्षा तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए

14 साल की उम्र अब संदेह से परे है। नोट संलग्न किया गया

शिक्षा संहिता (संशोधित) के खंड (xvi), पैरा 1 के लिए

संस्करण, 1958), अन्य बातों के साथ, प्रदान करता है कि बुनियादी स्कूलों में शामिल हैं कक्षा I से VIII तक के एकल विद्यालय। हमारे विचार में, यदि यू. पी. का एक कनिष्ठ राज्य v.

पवन कुमार द्विवेदी

[आर. एम. लोधा, सीजेआई]

बेसिक स्कूल (कक्षा I से V) प्राप्त करने के बाद जोड़ा जाता है।

स्कूल (कक्षा छठी से आठवीं), फिर निश्चित रूप से ऐसा जूनियर बेसिक स्कूल यह एक विद्यालय का अभिन्न अंग बन जाता है, अर्थात बुनियादी विद्यालय

कक्षा I से VIII तक। अभिव्यक्ति "जूनियर हाई स्कूल" में

1978 अधिनियम का उद्देश्य बुनियादी शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को संदर्भित करना है।

शिक्षा, अर्थात आठवीं कक्षा तक की शिक्षा। हमें नहीं लगता कि

"जूनियर" अभिव्यक्ति को संकीर्ण अर्थ देने के लिए उपयुक्त

हाई स्कूल "जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तर्क दिया गया है

राज्य। उस विधानमंडल ने जूनियर हाई अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया

स्कूल और न कि बुनियादी स्कूल जैसा कि उपयोग किया जाता है और परिभाषित किया जाता है

1972 हमारे विचार में अधिनियम महत्वहीन है। वह दृश्य, जो हमारे पास है

इसे इस तथ्य से मजबूत किया जाता है कि 1978 के अधिनियम की धारा 2 (जे) में,

1972 के अधिनियम में परिभाषित अभिव्यक्तियों को शामिल किया गया है।

45. श्री पी. पी. राव की प्रस्तुति, विद्वान वरिष्ठ

विषय के संदर्भ में यू. पी. राज्य के लिए वकील

रियाज जूनियर हाई स्कूल (छठी से आठवीं कक्षा),

कि उक्त विद्यालय शुरू में एक निजी मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त था

स्कूल और प्राथमिक खंड (कक्षा I से V) खोला गया था।

अलग प्राप्त करने के बाद प्रबंधन द्वारा मान्यता, जो गैर-सहायता प्राप्त थी, ऐसे प्राथमिक के शिक्षकों को

धारा, के नियम 2 (बी) और नियम 4 में परिभाषा के संदर्भ में

1975 नियम धारा 10 के लाभों के हकदार नहीं हैं

1978 हम जो पहले ही कह चुके हैं, उसके लिए अधिनियम हमें आकर्षित नहीं करता है ऊपर। उच्च न्यायालय द्वारा पहले दौर में लिया गया दृष्टिकोण

विनोद शर्मा 1 ने कहा कि संस्थान में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाया जाता था।

मुफ्त से संबंधित संवैधानिक योजना के अनुरूपता 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा।

46. हालांकि संदर्भ आदेश में, दोनों-न्यायाधीश पीठ

उच्च न्यायालय ने विनोद सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में पहले दौर में यह टिप्पणी की है।

13 एस सी आर।

शर्मा ने इस बात की सराहना नहीं की कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा

जूनियर हाई स्कूल स्तर से अलग कर दिया गया है

और अलग से विभिन्न अधिनियमों के तहत सौंपा गया

1972 के अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित बोर्ड और

यही बोर्ड जूनियर बेसिक स्कूलों पर नियंत्रण रखता है और यह विधानमंडल द्वारा किया गया एक सचेत अंतर था

विद्यालयों के दो समूह और उन्हें दो अलग-अलग घटकों के साथ व्यवहार करें

और इसलिए, विनोद शर्मा 'सही दृष्टिकोण नहीं लेते हैं।

लेकिन हम सोचते हैं कि संदर्भ क्रम में उल्लिखित विशेषताएँ

विनोद शर्मा 1 में लिए गए दृष्टिकोण को बुरा नहीं बताते हैं। हम पाते हैं।

डॉ. एम. पी. राजू के तर्क में योग्यता कि स्कूलों के पास है

जूनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल भी

अलग-अलग या एक साथ एक ही बोर्ड के तहत हैं, अर्थात

बुनियादी शिक्षा बोर्ड, 1972 के अधिनियम के अनुसार। इसके अलावा, कोई अन्य दृष्टिकोण 1978 के अधिनियम के प्रावधानों को प्रस्तुत कर सकता है।

भेदभाव के आधार पर असंवैधानिक। हमारे देश में

सुविचारित दृष्टिकोण, कोई भी व्याख्या जो प्रावधान की असंवैधानिकता से बचा जाना चाहिए। हम पकड़ते हैं,

जैसा कि यह होना चाहिए, कि जूनियर हाई स्कूल में अनिवार्य रूप से शामिल हैं

कक्षा I से V तक जब वे एक वरिष्ठ बुनियादी विद्यालय में खोले जाते हैं

(कक्षा VI से VIII) अलग मान्यता प्राप्त करने के बाद और जिसके लिए अनुदान-सहायता का एक अलग आदेश नहीं हो सकता है

सरकार ने।

47. हम तदनुसार तीनों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।

विनोद शर्मा 1 में न्यायाधीश पीठ। सवाल का हमारा जवाब

सकारात्मक है।

48. चूंकि इन अपीलों का भाग्य इस पर निर्भर करता है कि

हमने जो जवाब दिया है, हमें नहीं लगता कि यह आवश्यक है

इन अपीलों को नियमित पीठ को भेजें। ये हैं याचिकाएं

लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया।

याचिकाएं

खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस